



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 जून, 1994/28 ज्येष्ठ, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 26 अप्रैल, 1994

बंधा नी ० स० ० एच०-६८०५०(५)१९/९४—क्योंकि श्री अशोक कुमार, निवासी मेवा कोहलां की काश्त पर उपायुक्त ऊना द्वारा छानबीन करवाने पर, श्री संध्या दास, प्रधान, ग्राम पंचायत शोयल, विकास एवं गणराज द्वारा दिनांक १५-६-९२ को जन्म-मृत्यु पंजीकृत रजिस्टर के देखे चिना श्रीमती चिन्ती देवी श्री लक्ष्मण दस्त कोहला, ग्राम नदा कोहला का जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया जिसमें जन्म तिथि ३-६-१८९५ दर्शाई गई है। श्री रमेश चिकित्सा अधिकारी ऊना द्वारा दिनांक ३-६-९२ को जारी प्रमाण-पत्र द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना जिला की अम्ब तहसील के शोयल स्थानीय क्षेत्र के बंद १८९५ से अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों की तसाखी करने पर, श्रीमती चिन्ती देवी सुपुत्री सज्जमन दास का जन्म रजिस्ट्रीकरण न होने के अरोप में दोषी पाया गया।

क्योंकि दिनांक २-१२-९३ को प्रारम्भिक जांच के दौरान उक्त प्राप्त वर्ष १८९५ से सम्बन्धित जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर जिसके मनूसार प्रमाण-पत्र जारी किया है को प्रस्तुत करने में असफल रहा जिसके लिए उन्हें उपायुक्त ऊना ने दिनांक २०-१२-९३ को काला बताओ नौटिस जारी किया।

और क्योंकि प्रधान का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया तथा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मामले को सत्यता जानने के लिए नियमित जांच का करवाया जाना जनहित में उचित होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जो फि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54 के अधीन प्रदत्त है के प्रयोग में श्री संध्या दास, प्रधान, ग्राम पंचायत श्रीयत बिकाम खण्ड गवरेट, जिला ऊन के बिलुड नॉर्थ भूमि-मूर्डलाविकारी (ना०) अन्व को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं जो अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करने के माध्यम से शीघ्र भेज देंगे वहां पंजायत निरीक्षण, बिहार खण्ड गवरेट को प्रस्तुत कर्ता और नियुक्त करते हैं जो जांच के दौरान सरकार का पक्ष भी रखेंगे।

हस्ताक्षरित-  
प्रतिरिक्त सचिव।

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH

### "OFFICE ORDER"

Shimla-1, the 30th May, 1994

No. HIM/TP-Delegation of powers/93-Vol-1-1816-96—In exercise of the powers vested in the undersigned vide Sub-Section-2 of Section-77 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), I hereby delegate powers as exercisable by the undersigned under Section-38, 39, 79 and 81 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) in respect of Shimla Planning Area Zone No. 4, 5 and 6 as delineated in the Interim Development Plan Shimla, already notified vide Govt. of H. P. Notification No. 9-12/72-PW (B) dated 24-3-1979 to Er. Anil Biswas, Executive Engineer, Development Control Division No III (West) in supersession of this office order No. HIM/TP-Delegation of Powers/93-267-335, dated 18-4-1994.

Shimla-1, the 30th May, 1994

No HIM/Tp-Delegation of Powers/93-Vol-I-1897-1977.—In exercise of the powers vested in the undersigned vide Sub-Section-2 of Section-77 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), I hereby delegate powers as exercisable by the undersigned under section-38, 39, 79 and 81 of the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) in respect of Shimla Planning Area Zone No. 1, 2, 3 and 7 as delineated in the Interim Development Plan, Shimla already notified vide Government of Himachal Pradesh, Notification No. 9-12/72-PW (B) dated 24-3-1979 to Er. P. K. Latawa, Executive Engineer, Development Control Division No IV (East) in supersession of this office order No. HIM/Tp-Delegation of Powers/93-267-335 dated 18-4-1994.

Sd/-

Director,  
Town & Country Planning Deptt.

स्थानीय स्वशासन विभाग

ग्रामपाल

शिमला-2, 8 जून, 1994

संध्या 1-21/71-एल 0एम0जी 0.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान, श्रीर भूमि (वेदवली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का 22) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, वन विभाग के सभी वन मण्डल अधिकारियों को जहां तक वन भवि के अधिकमण और अप्राधिकृत अधिभोग का सम्बन्ध है अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के अर्द्धान कृत्यों के पालन के लिए, तत्काल प्रभाव से क्लबटर नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,

एस० के० सूद,  
आयुक्त एवं सचिव ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. 1-21/71-L.S.G. dated 8-6-94 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

## LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th June, 1994

No. 1-21/71-L.S.G.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Himachal Pradesh Public Premises & Land (Eviction & Rent Recovery) Act, 1971 (Act No. 22 of 1971) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint all the Divisional Forest Officers of the Forest Department to perform the functions of the Collector within their jurisdiction under the aforesaid Act in so far as the encroachments as well as un-authorised occupation of Forest Land is concerned, with immediate effect.

By order,

S. K. SOOD,  
Commissioner-cum-Secretary.

### मामान्य प्रशासन विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 8 जून, 1994

संख्या जी० ए० डी० (एफ०) १ (ए०) ४-२/९०-बण्ड-१.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार को संयक्त रूप से किए गए आवेदन पर पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 5 की उप-धारा (१) के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश देते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्यीय कामगार राहत निधि जिसे बाद में हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी वल्याण निधि के रूप में पुनः नामित किया गया है, तुरन्त प्रभाव से समाप्त हो जाएगी और उक्त निधि से सम्बन्धित सभी सम्पत्तियां और निधियां हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण निधि के अन्तर्गत से सुजित किए जाने के लिए प्रस्तुतिवित तये विनायक में निहित होंगी। उक्त निधि का प्रशासन नियन्त्रित किया जाएगा। जब तक कि पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 के अधीन इसके प्रशासन के लिए व्यवस्था नहीं देकी जाती।

- (i) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
- (ii) बित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।

- (iii) सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), हिमाचल प्रदेश।  
 (iv) सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रारंभ के आनन्द,  
मुख्य सचिव।

## GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 8th June, 1994.*

No. GAD (F)1(A)4-2/90-Part-I.—On the joint application made to the Government of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 21 of the General Clauses Act, 1897, read with sub-section (1) of section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Act No. VI of 1890), is pleased to order that Himachal Pradesh National Worker Relief Fund, subsequently renamed as the Himachal Pradesh Freedom Fighter's Welfare Fund, shall henceforth stand abolished and all property and funds heretofore belonging to the said Fund shall vest in the new endowment proposed to be created in the name of the Himachal Pradesh Freedom Fighter's Welfare Fund. The said Fund will be administered by a committee consisting of :—

- (i) Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.
- (ii) Finance Secretary to Government of Himachal Pradesh.
- (iii) Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh.
- (iv) Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.

till a detailed revised scheme for its operation under the Charitable Endowments Act, 1890, has been finalised.

R. K. ANAND,  
*Chief Secretary,*

### सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना नं. १  
शिमला: १७१००२, ८ जून, १९९४

संख्या जी० ए० डी० (ए०) ४-२/९०-पार्ट-१—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्व विद्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वरत् हुए, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, सचिव (सामान्य प्रशासन) और सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण निधि के प्रशासक के रूप में उनकी व्यक्तिगत हैसिखत में संमुक्त हैं। से निए गए आवेदन पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सा० प्र० वि० (ए०) १ (ए०) ४-२/९०-पार्ट-१ के दिनांक ८-६-९४ द्वारा हिमाचल प्रदेश के पूर्व विद्यासों के कोषाइयक में निहित होने वाली सम्पत्ति के प्रशासन के लिए नीचे दी गई योजना बनाते हैं :—

**हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण निधि के उपयोग के लिए योजना**

1. परिभाषा।—(क) “हिताधिकारी” जब तक कि मन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो “हित से हिमाचल प्रदेश में धर्मिवासित एसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष या देश की स्वतन्त्रता के लिए दुख सहे हों और यातना तथा कारण, स्वास्थ्य हानि, व्यहानि या सम्पत्ति की हानि का कारण जीवन योग्य करने की अवस्था में नहीं है।

(ख) “आश्रितों” से पत्ती और हिताधिकारी से सीधे तौर पर जुड़ वंशज और ऐसा अन्य व्यक्ति जिसने इसमें इसके पश्चात् राज्य बोर्ड कहा गया है। व्यक्ति या भागतः हिताधिकारी पर आश्रित है या आश्रित था, अभिप्रेत है।

2. योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(क) निधि में अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, और अन्य सरकारों से अभिदाय प्राप्त करना।

(ख) निधि के लिए निजि अभिदाय और दान इकट्ठा करना।

(ग) सभी उचित खर्चों, प्रभारों और व्ययों को चुकाना।

(घ) ऐसे अन्य कार्य करना जो ऊपर विवरणित उद्देश्यों को प्राप्त करने और यो क्रियान्वित करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हैं।

(ङ) हिताधिकारियों और उनके आश्रितों की प्रसुविधा के लिए समय निधि और/वा उपयोग करना।

3. निधि का प्रशासन पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिए बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसका गठन त्रैमासिक रूप में होगा।

4. राज्य बोर्ड की बैठक में गणपूर्ति बोर्ड के माठ प्रतिशत सदस्यों से होती है।

5. राज्य बोर्ड अपने कारोबार के संबंधित हेतु नियम बनाने के लिए सक्षम होगा।

6. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार बोर्ड के पदेन सचिव होंगे। वह राज्य बोर्ड द्वारा नीतियों के अनुसार राज्य बोर्ड के कारोबार का संचालन करने और निधि के दिन-प्रतिदिन के प्रदायी होगा। राज्य बोर्ड का सचिव इन योजना के अधीन अपने नभी और किन्हीं कृत्यों को प्रदेश सरकार के दिसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए सक्षम होगा।

7. राज्य बोर्ड हिमाचल प्रदेश सरकार के ऐसे अन्य अधिकारियों/वक्तारियों को उनके किन्हीं वार्ताओं का निर्वहन करने हेतु प्राविकृत करने के लिए सक्षम होगा।

8. राज्य बोर्ड समय-समय पर सलाहकार समितियों का गठन कर सकेगा और उन्हें भंग करने के प्रशासन या इनके प्रशासन से सम्बन्धित प्रश्नों पर परामर्श देने के लिए जिता संयोजकों का सुकृता है और हटा सकता है।

9. राज्य बोर्ड सभी रामयों पर पूर्व विनास अधिनियम, 1890 की धारा 13 के अधीन सभी नियमों के अनुरूप कार्य करेगा और उनका पालन करेगा।

10. योजना उस दिन प्रवर्तित होगी जिस दिन अपेक्षित निहित किया जाने वाला श्राद्ध राजपत्र में अधिसूचित होगा।

अनुवन्ध "अ"

### राज्य बोर्ड का गठन

1. राज्य बोर्ड हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा।

2. गठन : राज्य बोर्ड निम्नलिखित रूप से गठित होगा :

(i) अध्यक्ष

(ii) उपाध्यक्ष : अध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से उप-मन्त्रियों/उप-मन्त्रियों/सदस्य स्वतन्त्रता सेनानियों में से नाम निर्दिष्ट।

(iii) सदस्य

अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट बीस से अनधिक सदस्य।

(iv) परंपरा सदस्य

मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।

3. (i) सदस्यता की अवधि एक वर्ष की होगी परन्तु अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अवधि के अवसान में पूर्व हटा सकता है।

(ii) सदस्य पुनः अपनी अवधि के अवसान के पश्चात् पुनः नाम निवेशन के लिए पात्र हो जाएगा।

4. राज्य बोर्ड की बैठक जितनी भी बार करनी हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी परन्तु प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होंगी।

प्रार० के ० आनन्द,  
मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of Government Notification No. GAD (F) I (A) 4-2/90-I, dated 8th June, 1994 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

### GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th June, 1994.

No. GAD (F) I (A) 4-2/90-I.—On a joint application made by the Chief Secretary, Finance Secretary, Secretary (GAD) and Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, in their personal capacity as Administrators of the Himachal Pradesh Freedom Fighters Welfare Fund, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Act No. VI of 1890), to settle the scheme set forth below for the administration of the property to be vested in the Treasury Charitable Endowments, Himachal Pradesh vide Himachal Pradesh Government Notification No. GAD (F) I (A) 4-2/90-I, dated 8th June, 1994.

1910

**SCHEME FOR THE UTILISATION OF THE HIMACHAL PRADESH  
FREEDOM FIGHTERS WELFARE FUND**

**1. Definition.**—(a) "Beneficiary"—Unless the context otherwise requires "beneficiary" means a person of Himachal Pradesh domicile who has suffered during or on account of the struggle for the National liberation, and is not in a position to make his both ends meet due to loss of health by harassment or incarceration, loss of profession or loss of property.

(b) "Dependents" shall mean the wife and direct descendants of the beneficiary and any other person, who, in the opinion of Himachal Pradesh Freedom Fighters Welfare Board, hereinafter referred to as the State Board, is or was wholly or partly dependent on the beneficiary.

**2. The objects of the Scheme are as follows:**

- (a) To receive from the Central Government, Himachal Pradesh Government and other State Governments contributions in the shape of grants to the Fund.
- (b) To collect private contributions and donations for the Fund.
- (c) To defray all proper costs, charges and expenses.
- (d) To do all such other things as are incidental or conducive to the attainment of the objects mentioned above or any of the or to the carrying out of this Scheme.
- (e) To apply the corpus and/or income of the Fund for the benefit of the beneficiaries and their dependents.

**3. The Fund shall be administered for the objects aforesaid by a State Board which will be constituted as specified in Annexure 'A'.**

**4. The quorum at any meeting of the State Board shall consist of 60 percent to the members of the Board.**

**5. The State Board shall be competent to make rules for the conduct of its business.**

**6. The Chief Secretary to the Government, Himachal Pradesh shall be the ex-officio Secretary of the State Board. He shall be responsible for conducting the business of the State Board and for the day to day administration of the fund, in accordance with the policies laid down by the State Board. It shall be competent for the Secretary of the State Board to delegate all or any of his functions under this Scheme to any other officer of the Himachal Pradesh Government.**

**7. The State Board shall be competent to authorise such other officers/officials of the Himachal Pradesh Government to discharge any of their ministerial functions.**

**8. The State board may, from time to time, constitute and dissolve Advisory Committees, appoint or remove district conveners for advising them on the administration of the Fund or any question connected with the administration thereof.**

**9. The State Board shall at all times conform and abide by rules framed under section 13 of the Charitable Endowments Act, 1890.**

10. The Scheme shall come in to operation on the day the requisite vesting order is notified in the Rajpátra.

#### ANNEXURE 'A'

#### CONSTITUTION OF THE STATE BOARD

1. The State Board shall be known as the Himachal Pradesh Freedom Fighters Welfare Board.

2. *Composition*.—The State Board shall be constituted as under:

(i) President	The Chief Minister, Himachal Pradesh,
(ii) Vice-President	To be nominated by the President from amongst Ministers/Deputy Ministers/Freedom Fighter Members.
(iii) Members	Members not exceeding 20(Twenty) to be nominated by the President.
(iv) Ex-Officio Secretary	The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.

3. (i) The term of membership will be one year provided that the President may remove any member before the expiry of the term.

(ii) A member will be eligible for renomination on the expiry of his term.

4. The State Board shall meet as often as may called by the President, but at least two meetings shall take place in each year.

R. K. ANAND  
Chief Secretary.

सामाजिक प्रशासन विभाग

एफ-शाब्दा

भवित्वाचना

गिमला-2, 9 जून, 1994

मंड़ा सं० प्र० ५० (एक) १(ए) ४-२/९०-१.—मुख्य मंत्री महोदय जी कि हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के व्यवस्था है को हैमियत से इस बोर्ड में नियन्त्रिति सदस्यों को एवं अधिसूचना के लिए सहर्ष मनोनीत "करते हैं।"

1. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश

2. श्री गोरी प्रसाद, महाजन बाजार, मण्डी  
जिला मण्डी (हि० प्र०)

3. महारथ तीर्थ राम, गंधी सेवा आश्रम  
घोटल, जिला झज्जा (हि० प्र०)

मध्यस्थ

उपाध्यक्ष

सदस्य

5.	श्रीमती सरला शर्मा, स्टेबरी हिल, हार्डिंग बोड क्लोनी, शिमला-2।	सदस्य
6.	श्री नरोत्तम दत्त शास्त्री, जीवन कुटीर सेक्टर नं 3, विलासपुर (हि० प्र०)।	सदस्य
7.	श्री सीता राम शर्मा, पूर्व विधायक, गांव धारठ, डाकघर जावरी, तहसील विजित शिमला (हि० प्र०)।	सदस्य
8.	लाला भगत राम, गांव/डाकघर कड़ोहता, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।	सदस्य
9.	श्री बस्ती राम पहाड़िया, गांव पाल्, डाकघर हावण, तहसील राजगढ़, जिला विरामोर (हि० प्र०)।	सदस्य
10.	श्री राधा कृष्ण, गांव केलतान्दी, डाकघर चनोर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।	सदस्य
11.	श्री तेज मिह निधड़िक, मकान नं 165/7, मण्डी टाऊन, जिला मण्डी (हि० प्र०)।	सदस्य
12.	श्री देवी दास मुसाफिर, गांव जधौड़, डाकघर सरोग, तहसील पालमपुर/जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।	सदस्य
13.	श्री जान चन्द टट्टू निवासी टट्टू, शिमला-11	सदस्य
14.	श्री बदरी प्रसाद, गांव मनियारा, डाकघर पादा, तहसील पालमपुर/जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।	सदस्य
15.	श्री पद्म नाथ, गांव/डाकघर रिचालपुर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।	सदस्य
16.	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।	पदेन सचिव।

2. हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता मेनानी कल्याण बोर्ड के गैर-प्ररकारी सदस्यों को दैनिक एवं यात्रा भत्ता संलग्न अनुबंध के अनुसार देय होगा।
3. यह खर्च मुख्य शीर्षक "2235-प्रामाणिक सुरक्षा एवं कल्याण-200-प्रथ्य स्कीमें, 06-हिमाचल प्रदेश

4. संयुक्त सचिव/उपसचिव/ग्रवर सचिव (सामान्य प्रशासन) इस बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों के दैनिक भत्ता भत्ता भुवताने के लिए नियन्त्रक अधिकारी होंगे। इन सदस्यों के उपरोक्त बिल भी सामान्य प्रशासन विभाग एक-जात्या में बनाये जायेंगे।

5. इस मामले पर वित्त विभाग ने प्रपनी सहमति प्रतीपचारिक संघर्ष 531-Fin-(c)A-9/189-IV दिनांक 23-5-94 द्वारा प्रदान कर रखी है।

#### (क) रेल द्वारा यात्रा:

गैर-सरकारी सदस्य को प्रवर्म थेणी के सरकारी रूपवाली समाज मनुष्य जाएँगे और वस्तुतः प्रयोग की गई वीज युवेश के बीच के विवरणों के अनुसूचित जाइ के प्रतिरिक्त वास्तविक विवरण भाड़े का हकदार होगा।

#### (ख) सड़क द्वारा यात्रा:

यात्रा की दशा में सड़क मील दूरी, केंद्र जो रेल के साथ सम्बद्ध न हो; के बीच में, गैर-सरकारी सदस्य निम्न सड़क मील दूरी के हकदार होंगे:—

(I) यदि यात्रा वास्तविक भाड़ा देकर की गई हो—  
जैसे लोक बस द्वारा एकल सीट/स्थान

(II) मोटर साईकल/स्कटर द्वारा  
यात्रा की दशा में।

(III) पूरी टैक्सी या अपनी कार  
द्वारा यात्रा की दशा में।

(क) पहाड़ी/झेव 80 पैसे प्रति  
कि.0 मी0।

(ख) समतल/झेव 60 पैसे प्रति  
कि.0 मी0।

(क) पहाड़ी/झेव 2.50 पैसे प्रति  
कि.0 मी0।

(ख) समतल/झेव 2.00 रु प्रति  
कि.0 मी0।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उन्हे विभाग से प्रारम्भ होने वाले स्थाई निवास स्थान, से उनकी कुल अनुपस्थिति के लिए और स्थाई निवास स्थान पर पहुँचने की समाप्ति के साथ सरकारी रूपवाली को लागू निबन्धन और शर्तों और निम्न पैरा 5 की शर्तों के अध्याधीन दैनिक भत्ता मिलेगा।

#### 2. दैनिक भत्ते:

(क) गैर-सरकारी सदस्य बैठक के प्रत्येक दिन के अपने-अपने परिसर्वत्र और प्रथम थेणी के सरकारी कर्मचारियों को लागू होने वाले निबन्धन और शर्तों के अध्याधीन उच्च दर पर दैनिक भत्ता मिलेगा।

- (ख) बैठक के दिनों के लिए दैनिक भत्ते के अतिरिक्त सदस्य द्वारे पर और निम्न बोई/समिति के कार्यों से सम्बद्ध बाहरी स्टेशन पर विशेष के लिए दैनिक भत्ते का हकदार भी होगा :—
- (क) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक न हो
- (ख) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक पूर्ण तुलना 12 घण्टे 70 प्रतिशत से अधिक न हो ।
- (ग) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 12 घण्टे से अधिक है पूर्ण तुलना 3. (घ) प्रवहण भत्ता :

गैर-सरकारी सदस्य जो उस स्थान, जहां बोई/समिति की बैठक आयोजित होती है का निवासी हो, को यहां उपदण्डित मान पर यात्रा और दैनिक भत्ता जो अधिकारीतम् 10 रुपये प्रतिदिन हो लेने, तो हकदार नहीं होगा। इससे पहले कि यात्रा वस्तुतः संकेत लिया जाये (Controlling Officer) नियन्त्रक अधिकारी द्वारा को सत्यापित करेगा और ऐसा बौद्धि जिने अवश्यक नज़र अभिप्राप्त करके कि वास्तविक व्यय द्वारा की रूचि से कम नहीं थी अपना समाधान करेगा। यदि इस बौद्धि से उन्ना समाधान नहीं होता तो वह अपने विवेक पर प्रवहण भत्ते को गड़ी भी दी तरह जीमित कर भरेगा। यदि ऐसा सदस्य अपनी कार का प्रयोग करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के प्रविकारी को जीत दूरी भत्ता अनुसूत दर से अधिकतम् 10 रुपये प्रति दिन के अनुसार दिया जायेगा।

(4) सदस्य को यात्रा मार्ग दैनिक भत्ता उसके हारा डा भाव का प्रमाण पर पेज करने पर दिया जायेगा कि उसने उसी यात्रा के लिए तरकार के जिती अन्य क्षेत्र में यात्रा या इनिया भत्ता नहीं लिया है।

(5) गैर-सरकारी सदस्य बोई/समिति की बैठक से सम्बद्ध थी गई वास्तविक यात्रा के लिए और उसके स्थाई निवास स्थान जो पहले से ही न पिछ लिया गया हो यात्रा भत्ते का हकदार होगा। यदि कोई सदस्य बोई/समिति की बैठक में हजिर होने के लिए अर्थ स्थाई निवास स्थान में भिन्न अन्य स्थान पर यात्रा करे या बैठक समाप्त होने के पश्चात् उसके स्थाई निवास स्थान ने भिन्न अन्य स्थान या ऐसे अन्य स्थान और बैठक का स्थान, जिनकी दूरी कम है को वापिस आता है।

(6) गैर-सरकारी सदस्य को यात्रा भत्ते के खाते में अतिसंदेश की दजा में हिमाचल प्रदेश खजाना नियम के नियम 4.17 और 6.1 के उत्तरव्य यथा आवश्यक परिवर्तन लिहित लागू होंगे।

(7) गैर-सरकारी सदस्य जो विधान सभा का सदस्य हो, में बोई/समिति के काम से सम्बद्ध यात्रा की हो समझ-ममता पर संबोधित विधान सभा प्रधिनियम के अधीन अनुदेश के बैतरन और भत्ते के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(8) सदस्य उसके समन्वेशन से सम्बद्ध दैनिक भत्ते के लिए हकदार नहीं होता जब विधान सभा या विधान सभा समिति जिन पर गदस्य नक्त में विचारत है जैसे विधान सभा गदस्य के बैतरन और भत्ते के अधिनियम के अधीन वह अपने दैनिक भत्ते ले रहे हैं, हावाहि यदि वह प्रपाणित करे तो उन्हें सदन के सत्र या विधान सभा समिति के हाजिर होने से निवारित किया गया हो और विधान सभा से कोई दृष्टिकोण नहीं लिया है, वह विनियोग दर से दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(9) सदस्य जिसे विधान सभा से अनुहित लिया गया हो प्रवहण भत्ते के अन्तर्गत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी नहीं लगता।

शिमला-2, 9 जून, 1994

\* संख्या साठो प्र० विं०(एफ०) १(ए०) ४-२/९०-१.—इस विभाग की अधिसूचना समसंलग्न वित्तांक १३-५-९४ के क्रम को जारी रखते हुए स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के अधीन गठित उप-समिति के गैर-सकारी सदस्यों को दैनिक/यात्रा भत्ता संलग्न ग्रन्थबंधन के अनुसार देय होगा।

2. यह खंचा मुख्य शीर्षक 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-200—ग्रन्थ स्कीम, 06—हिन्दूचल प्रदेश स्वतंत्रना सेनानी कल्याण निधि से किया जायेगा। (गैर-योजना)।

3. संयुक्त सचिव/उप-पर्वती/अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) इस उप-समिति के गैर सरकारी सदस्यों के दैनिक/यात्रा भत्ता भुगताने के नियन्त्रण अधिकारी होंगे। इन सदस्यों के उपरोक्त बिल भी सामान्य प्रशासन एक-शाखा में बनाये जायेंगे।

4. इस मामले पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति अनौपचारिक संझा 531-फिन(सी)ए (9) 1/ 89-4, दिनांक 23-5-94 द्वारा प्राप्त कर रखी है।

85-4, 144-1, 23-3, 33-1, 44-1, 55-1, 66-1, 77-1, 88-1, 99-1

इस्ताधिक्षि/-

आयकृत एवं सचिव

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4000 or email at [mhwang@uiowa.edu](mailto:mhwang@uiowa.edu).

गह विभाग

अधिसंचार

शिमला-२, १० जून, १९९४

संख्या गृह (४०) एफ० (१३)-८/९०.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, मनोवेत कॉल्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी अभ्यास अधिनियम, १९३८ की धारा ९ की उपधारा (३) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (४) में अपेक्षित है, इस अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन उन सभी क्षेत्रों में जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना में स्थित गृह (४०) एफ० (१३)-८/९०, दिनांक २५-१०-७१ जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र के अंक दिनांक १०-१०-७१ में प्रकाशित हुई थी, में निर्दिष्ट ऐल-गए हैं, में विस्तृत अधिवित के दोरान पूर्व परिभासित क्षेत्र में फौल्ड फायरिंग एवं आर्टिलरी अभ्यास करने हेतु प्राधिकृत करने के निष्क्रम को, दुरकारी राजपत्र में इस आशय को अधिसूचना उन लोगों को सूचना हेतु जोहि इसके द्वारा प्रभावित होने सम्भावित है, सहर्ष प्रकाशित करते हैं।

<sup>1</sup> जुलाई, 1994 से 30 जून, 1995 (नारायण गढ़, रेज़) :

तोष दागने का अभ्यास एक सप्ताह में त्रिंश दिन यानि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा शुक्रवार को होगा। यदि फिली कारणवश इन चारों दिनों में से किसी दिन अवकाश होता है तो फायरिंग का अभ्यास नहीं होता।

अद्य विषय के अनुसार इस विभाग में विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं। आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित

आयुक्त एवं सचिव ।

## TRANSPORT DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-171002, the 10 June, 1994

No. 1-1/84-Pari.—In supersession of this Department's Notification of even number dated 24-5-1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-nominate Shri Prem Kaushal as member of Regional Transport Authority, Mandi and his tenure will coterminous with this Department's Notification Number 1-1/84-Pari, dated 24-5-1994.

By order,  
Sd/-  
Commissioner-cum-Secretary.

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 10 जून, 1994

संख्या पी० सी० एन०एम०एन०डी०ए(1)६१/९२-२२०३-२२०६.—यतः ग्राम पंचायत जडोल, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि० प्र० ने अपने प्रस्ताव संख्या ३, दिनांक १३-४-१९९४ के अन्तर्गत सूचित किया है कि श्री कातकु राम, पंच, वार्ड नं० ६ की मृत्यु दिनांक ४-१-१९९४ को हो गई, जिसके कारण ग्राम पंचायत जडोल के वार्ड नं० ६ में पंच का स्थान रिक्त हो गया है।

अतः मैं, ए० आर० रिजवी, अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, (हि० प्र०) ग्राम पंचायत जडोल के वार्ड नं० ६ में पंच का स्थान रिक्त घोषित करता हूँ।

मण्डी, 13 जून, 1994

संख्या पी० सी० एन०एम०एन०डी०ए(1)६१/९२-२२२३-२८.—उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 1971 के नियम 19(बी) जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-गी०सी०एच०एच०वी०-२)१९/७६, दिनांक १५-१-१९८२ के साथ पढ़ा जाये के अधीन प्राप्त है; मैं, ए० आर० रिजवी, अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, (हि० प्र०) निम्न पंचायत पदाधिकारियों के त्याग-पत्र स्वीकार करता हूँ साथ ही इनके पदों का रिक्त घोषित करता हूँ :—

क्रम संख्या	नाम	विकास खण्ड	नाम ग्राम पंचायत	नाम पदाधिकारी	पद	वार्ड संख्या
1.	चौतडा		लांगणा	श्री मेध सिंह	उप-प्रधान	
2.	चौतडा		लांगणा	श्री लाल सिंह	पंच	नेरी कोटला वार्ड नं० ५

ए० आर० रिजवी,

अतिरिक्त उपायुक्त,

मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

## M.P.P. AND POWER DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th June, 1994

No. MPP-C(3)10/88-Equity. HPSEB.—Whereas the Governor of Himachal Pradesh considers it expedient so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12-A<sup>c</sup> of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act No. 54 of 1948) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct that the Himachal Pradesh State Electricity Board shall be, with immediate effect, a body corporate with a capital of ten crores of rupees.

By order,

B. B. TANDON,  
Financial Commissioner-cum-Secretary.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

ऊना, 15 जून, 1994

संख्या एफ० डी० एस० ऊना-136/81-भाग-2/-3057-3156.—विष्टले तभी आदेशों का अधिकरण करते हुए, हिमाचल प्रदेश जनाधोरी तथा मनाकाखोरी निवारण अधिकारी, 1977 की घारा 3 (1) (ई) में प्रत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम० एल० शर्मा, हि० प्र० से० जिला दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, (हिमाचल प्रदेश) उपरोक्त आदेशों की अनुसूचि संबंधी में दर्ज निम्नलिखित वस्तुओं का समस्त कराँ सहित अधिकतम परचम मूल्य का निर्धारण निम्न प्रकार से करता हूँ। कोई भी व्यापारिक निमौता निम्न निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य नहीं लेगा।

क्र० सं०	आदेश के अनुसार वस्तु का नाम	गमले कर्णे सहित अधिकतम वर्तन मूल्य
१.	(शैडूयल) वस्तु क्रमांक १. डब्ल्यु रोटी लोकल वजन 400 ग्राम	३५० प्रति पैक्ट
२.	२. डब्ल्यु रोटी बाहर की वजन 400 ग्राम	३.७५ प्रति पैक्ट
२.	१. मीट बकरा	४०.०० प्रति किलोग्राम
	२. मीट बकरा	१६.०० प्रति प्लेट
	३. मीट मछली (ग्रेड-ए)	२७.०० प्रति किलोग्राम
	४. मीट मछली (ग्रेड-बी)	१८.०० प्रति किलोग्राम

1	2	3	4
3.	17.	1. खाना प्रति थाली चपाती, दाल सब्जी सहित 2. खाना प्रति प्लेट चावल दाल तथा सब्जी सहित 3. चपाती तन्दूरी 4. स्पैशल पनीर वाली सब्जी 5. स्पैशल सब्जी फुल प्लेट 6. दाल काइड	10.00 प्रति खुराक 10.00 प्रति खुराक 1.00 प्रति चपाती 8.00 प्रति प्लेट 7.00 प्रति प्लेट 4.00 प्रति प्लेट
4.	18.	1. दूध कच्चा हलवाईयों द्वारा बेचा जाना 2. दूध मीठा डाल कर 3. दही 4. दही लस्सी 5. पनीर	8.00 प्रति किलोग्राम 9.00 प्रति किलोग्राम 12.00 प्रति किलोग्राम 5.00 प्रति गिलास 50.00 प्रति किलोग्राम

## टिप्पणी :

दुकानदार को दुकान में सहज दृष्टिगत स्थान पर मूल्य सूचि प्रदर्शित करना और उस पर दुकानदार/भागीदार/प्रबन्धक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

यह आदेश सम्पूर्ण ज़िला ऊना में हिमाचल प्रदेश राज्यत में प्रकाशित होने से एक माह की अवधि तक लागू रहेगे।

एम० एल० शर्मा,  
ज़िला दण्डाधिकारी ऊना,  
ज़िला ऊना, (हिमाचल प्रदेश)।